

## वर्ष 2020 के बाद वैश्विक जैवविधिता फ्रेमवर्क में अंतराल

### प्रलिमिंस के लिये:

रासायनिक प्रदूषक, जलवायु शमन लक्ष्य ।

### मेन्स के लिये:

पोस्ट-2020 ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क में अंतराल और सफिराशैं ।

## चर्चा में क्यों?

पर्यावरण वैज्ञानिकों, पारस्थितिकीविदों और नीतिविशेषज्ञों के एक समूह ने माना है कि [वर्ष 2020 के बाद वैश्विक जैवविधिता फ्रेमवर्क](#) का मसौदा उन [रासायनिक प्रदूषकों](#) की समग्रता का हिसाब देने में वफिल है जो वैश्विक स्तर पर पारस्थितिक तंत्र को खतरे में डालते हैं ।

## फ्रेमवर्क में अंतराल:

- **रासायनिक प्रदूषक:** मसौदा समझौता पोषक तत्त्वों, कीटनाशकों और प्लास्टिक को शामिल करके सीमिति हो जाता है, क्योंकि **अधिक चिंता और महत्त्व के कई रसायनों को समूह से बाहर रखा जाता है**, जिसमें ऐसे पदार्थ शामिल हैं जो वषिकृत हैं, जैसे पारा और PFAS (प्रति पॉलीफ्लोरोएलकिलि पदार्थ) साथ ही फार्मास्यूटिकल्स ।
- **संरक्षित क्षेत्रों के अंदर LNPP:** वर्तमान में LNPP (भूमिजहाँ प्राकृतिक प्रक्रियाएँ परबल होती हैं) स्थायी बर्फ और चट्टान को छोड़कर लगभग 56% स्थलीय भूमि को कवर करती है । हालाँकि इस भूमिका केवल 20% ही औपचारिक रूप से संरक्षित है । इसका मतलब यह है कि स्थायी बर्फ और चट्टान को छोड़कर दुनिया की केवल 11% भूमि LNPP द्वारा संरक्षित क्षेत्रों के अंदर है । समूह को लगता है कि यह **एकसमस्या है क्योंकि वर्ष 2020 के बाद के ढाँचे में वर्ष 2030 तक कम से कम 30% भूमि की रक्षा करने का प्रस्ताव है** ।
  - LNPP उस भूमि को संदरभति करता है जहाँ कम मानवीय हस्तक्षेप और / या पारस्थितिक रूप से अपेक्षाकृत यथावत वनस्पति है, जो जैवविधिता को पनपने के लिये स्थान और आवास प्रदान करती है ।

## वर्ष 2020 के बाद वैश्विक जैवविधिता फ्रेमवर्क

- **परचिय:**
  - यह एक नया फ्रेमवर्क है जो लोगों को प्रकृति और इसकी आवश्यक सेवाओं को पररिक्षित तथा संरक्षित करने के लिये **वर्ष 2030 तक दुनिया भर में कार्यों का मार्गदर्शन करेगा** ।
  - इसका उद्देश्य सरकारों और पूरे समाज द्वारा जैवविधिता, इसके प्रोटोकॉल और जैवविधिता से संबंधित अन्य बहुपक्षीय समझौतों, प्रक्रियाओं और उपकरणों के उद्देश्यों में योगदान करने के लिये तत्काल तथा परविरतनकारी कार्रवाई को बढ़ावा देना है ।
  - फ्रेमवर्क परविरतन के सिद्धांत के इर्द-गिर्द बनाया गया है जो यह मानता है कि आर्थिक, सामाजिक और वित्तीय मॉडल को बदलने के लिये वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर तत्काल नीतिगत कार्रवाई की आवश्यकता है ।
- **लक्ष्य और उद्देश्य:**
  - **वर्ष 2050 तक हासिल करने के लिये चार लक्ष्य:**
    - जैवविधिता के वल्लिपुत होने और गरिवट को रोकने के लिये ।
    - संरक्षण के द्वारा मनुष्यों को प्रकृति की सेवाओं में वृद्धि और बनाए रखने के लिये ।
    - आनुवंशिक संसाधनों के उपयोग से सभी को उचित और समान लाभ सुनिश्चित करना ।
    - उपलब्ध वित्तीय और कार्यान्वयन के अन्य साधनों तथा वर्ष 2050 के वजिन को प्राप्त करने के लिये आवश्यक बीच की अंतराल को पाटना ।
  - **2030 कार्य लक्ष्य:** वर्ष 2030 के दशक में तत्काल कार्रवाई के लिये ढाँचे में 21 कार्योंमुख लक्ष्य हैं, जिनमें शामिल हैं:
    - विश्व के कम से कम 30% भूमि और समुद्री क्षेत्र को संरक्षित क्षेत्रों के अंतर्गत लाना ।
    - आक्रामक वदिशी प्रजातियों की शुरुआत की दर में 50% से अधिक कमी, और उनके प्रभावों को खत्म करने या कम करने के लिये

ऐसी प्रजातियों का नयितरण या उन्मूलन।

- पर्यावरण के लिये नुकसानदेह पोषक तत्वों को कम से कम आधा, और कीटनाशकों को कम से कम दो तहई कम करना, और प्लास्टिक कचरे के नरि्वहन को समाप्त करना।
- प्रतिवर्ष कम से कम 10 GtCO<sub>2</sub>e (गीगाटन समतुल्य कार्बन डाइऑक्साइड) के वैश्विक जलवायु परिवर्तन शमन प्रयासों में प्रकृति-आधारित योगदान, और यह कसिभी शमन तथा अनुकूलन प्रयास जैवविधिता पर नकारात्मक प्रभावों से बचाते हैं।
- जैवविधिता के लिये हानिकारक प्रोत्साहनों को पुनर्निर्देशित, पुनः उपयोग, सुधार या समाप्त करना, उचित और न्यायसंगत तरीके से, उन्हें प्रतिवर्ष कम से कम 500 बलियन अमेरिकी डॉलर तक कम करना।

## अनुशासऱै:

- वर्ष 2020 के बाद के वैश्विक जैवविधिता फ्रेमवर्क में लागू की जाने वाली रणनीतियों और कार्रवाई के लिये रासायनिक प्रदूषकों के व्यापक दायरे को लक्षित करने की आवश्यकता है।
  - दुनिया भर के देश हाल ही में मौजूदा ज्ञान को समेकित करने और नीतिनिर्माताओं को सूचित करने के लिये रसायनों और कचरे पर एक अंतर-सरकारी वजिज्ञान-नीति पैनल बनाने पर सहमत हुए हैं।
- दूरदराज के आर्कटिक, अंटार्कटिक और हमिलयी पारस्थितिक तंत्र सहित दुनिया के हर पारस्थितिक तंत्र में पाए जाने वाले रासायनिक प्रदूषकों के अकाट्य प्रमाण, नए जैवविधिता फ्रेमवर्क के वार्ताकारों को इन्हें वैश्विक जैवविधिता के लिये खतरों के रूप में शामिल करने हेतु मज़बूर करना चाहिये।
- भोजन की उपलब्धता के लिये जैवविधिता की रक्षा करना महत्त्वपूर्ण है, सभी प्रजातियों की स्वस्थ और लचीली आबादी का समर्थन करने के लिये वर्ष 2030 तक कम-से-कम 5% और 2050 तक 15% की प्राकृतिक प्रणालियों के कषेत्र, कनेक्टिविटी और अखंडता में शुद्ध लाभ होना चाहिये।
- आहार में बदलाव, फसल और पशुधन उत्पादकता में वृद्धि और कृषिभूमि के वसितार को सीमित करने से वर्ष 2050 तक वैश्विक जैवविधिता, खाद्य सुरक्षा और जलवायु शमन लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मल्लिगी।

## जैवविधिता अभसिमय (CBD)

- जैवविधिता अभसिमय (Convention on Biological Diversity- CBD), जैवविधिता के संरक्षण हेतु कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि है जो वर्ष 1993 से लागू है। इसके 3 मुख्य उद्देश्य हैं:
  - जैवविधिता का संरक्षण।
  - जैविक विधिता के घटकों का सतत उपयोग।
  - आनुवंशिक संसाधनों के उपयोग से होने वाले लाभों का उचित और न्यायसंगत वितरण।
- लगभग सभी देशों ने इसकी पुष्टि की है (अमेरिका ने इस संधि पर हस्ताक्षर तो किये हैं लेकिन पुष्टि नहीं की है)।
- CBD का सचिवालय मॉन्ट्रियल, कनाडा में स्थित है जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के तहत संचालित होता है।
- जैवविधिता अभसिमय के तहत पार्टियाँ (देश) नियमित अंतराल पर मल्लिती हैं और इन बैठकों को कॉन्फरेंस ऑफ पार्टिज़ (Conference of Parties - COP) कहा जाता है।
- वर्ष 2000 में जैव सुरक्षा पर एक पूरक समझौते के रूप में [कार्टाजेना प्रोटोकॉल](#) (Cartagena Protocol on Biosafety) को अपनाया गया था। यह 11 सितंबर, 2003 को लागू हुआ।
  - यह प्रोटोकॉल आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी के परिणामस्वरूप संशोधित जीवित जीवों द्वारा उत्पन्न संभावित जोखिमों से जैविक विधिता की रक्षा करता है।
  - आनुवंशिक संसाधनों तक पहुँच सुनिश्चित तकरने और उनके उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों के उचित एवं न्यायसंगत साझाकरण को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2010 में नागोया प्रोटोकॉल को जापान के नागोया शहर में संपन्न।
- नागोया प्रोटोकॉल COP10 में अपनाया गया था। यह 12 अक्टूबर, 2014 को लागू हुआ।
  - यह प्रोटोकॉल न केवल CBD के तहत शामिल आनुवंशिक संसाधनों और उनके उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों पर लागू होता है, बल्कि आनुवंशिक संसाधनों से जुड़े उस पारंपरिक ज्ञान (Traditional knowledge- TK) को भी कवर करता है जो CBD और इसके उपयोग से होने वाले लाभों से आच्छादित हैं।
- COP-10 में आनुवंशिक संसाधनों पर [नागोया प्रोटोकॉल](#) को अपनाने के साथ, जैवविधिता को बचाने हेतु सभी देशों द्वारा कार्रवाई के लिये दस वर्ष की रूपरेख को भी अपनाया गया।
- वर्ष 2010 में नागोया में CBD की [कॉन्फरेंस ऑफ पार्टिज़](#) (COP-10) में वर्ष 2011-2020 हेतु 'जैवविधिता के लिये रणनीतिक योजना' को अपनाया गया। इसमें पहली बार वषिय वशिषिट 20 जैवविधिता लक्ष्यों- जनिहें [आइसी जैवविधिता लक्ष्य](#) के रूप में भी जाना जाता है, को अपनाया गया।
- भारत में CBD के प्रावधानों को प्रभावी बनाने हेतु वर्ष 2002 में जैविक विधिता अधिनियम अधिनियमित किया गया।

## स्रोत: डाउन टू अर्थ

